फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 45 प्रभात जयपुर, मंगलवार 15 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

# राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

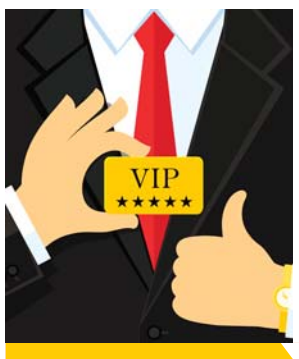


**Time Waited Away**

I was saved a four hour early start. Was this fair? Was it not a fraud to take advantage of my punctuality?

**Keys, Buttons! Not Original**

**The Global Rise of Indian Hand Embroidery**

One of the most celebrated examples of Chankaya's artistry came during the Dior Fall 2023 Show hosted by Dior at the iconic Gateway of India

# 'एक देश पर निर्भरता को छोड़कर, दूसरे देश पर निर्भर हो जाना प्रगति नहीं'

## ब्रिक्स सम्मेलन में भारत व चीन का एक-दूसरे के प्रति अविश्वास साफ दिखा, पर, इसके बावजूद दोनों देशों ने आपस में व्यवसायिक संबंधों को आगे बढ़ाने में इस अविश्वास को आड़े नहीं आने दिया

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। जहां भारतीय मीडिया ने ब्रिक्स के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के नतीजों को भारत के लिए रणनीतिक फायदे के तौर पर पेश किया है, वहीं, "साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट" की एक रिपोर्ट में एक दिलचस्प विरोधाभास की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह ने अमेरिका के टैरिफ, प्रतिबंधों और डॉलर के दबदबे के खिलाफ एकजुट रुख दिखाया, फिर भी इसके दो सबसे प्रभावशाली सदस्य, चीन और भारत ने इसके भीतर मौजूद रणनीतिक तनाव को उजागर किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सदस्यों को ओपन-सोर्स आर्टिफिशल इंटैलिजैंस और स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग में सहयोग की पेशकश की, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चेतावनी दी कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का इस्तेमाल "हथियार" के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। इस आदान-प्रदान ने ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ उसकी एकता की सीमाओं को भी रेखांकित किया है।

- **भारत ने बीच का रास्ता निकालते हुए नारा दिया कि आर्थिक विकास का हथियारीकरण नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए चीन चुंबक बनाने के लिए रेअर अर्थ खनिज की सप्लाई को जब चाहे अवरूद्ध कर सकता है और अमेरिका "चिप्स" की अपनी ताकत का उपयोग कर "चिप्स मैन्युफैक्चरिंग" का गला घोट सकता है। अतः ब्रिक्स ओद्यौगिक उत्पादन के "वैपनाइज़ेशन" (हथियारीकरण) के खिलाफ है।**
- **भारत का मैसेज था, भारत ब्रिक्स का सहयोग चाहता है, पर, साथ ही पश्चिमी देशों पर या चीन पर निर्भर नहीं रहने की नीति अपना रहा है।**

शी ने इस सम्मेलन का इस्तेमाल चीन को "ग्लोबल साउथ" के लिए एक तकनीकी साझेदार के रूप में पेश करने के लिए किया। उन्होंने ओपन सोर्स ए.आई. और स्मार्ट कारखानों में सहयोग का प्रस्ताव रखा, साथ ही सदस्य देशों के युवाओं को एडवांस्ड टैक्नॉलजी और इनोवेशन में ट्रेनिंग देने की बात की। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भू-राजनीतिक उथल-पुथल से आपूर्ति और इण्डस्ट्रियल चेन की सुराक्षा के लिए सहयोग मजबूत करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियम सभी देशों को मिलकर बनाने चाहिए और उन्हें बिना दोहरे मापदंड के लागू किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिफिशल इंटैलिजैंस का प्रस्ताव रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैक्नॉलजी की दौड़ अब तेजी से चिप्स, खनिजों, मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों और सप्लाई चेन पर नियंत्रण के इर्द-गिर्द घूम रही है। चीन का बैटरी, चुंबक और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए जरूरी कई खनिजों और मैन्युफैक्चरिंग इनपुट पर दबदबा है, जबकि अमेरिका एडवांस्ड चिप और चिप बनाने वाले उपकरणों का प्रमुख सप्लायर और नियंत्रक बना हुआ है। इसलिए "ग्लोबल साउथ" के देशों के सामने किसी एक शक्ति पर निर्भर होने का खतरा है।

मोदी की चेतावनी सीधे तौर पर इसी दुविधा पर केन्द्रित थी। चीन या अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जिला उपभोक्ता आयोग ने मारूति पर दो लाख रूपए का जुर्माना लगाया

जयपुर, 14 सितम्बर। जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम ने कार में उत्पादकीय दोष होने व एक्सीडेंट में एयरबैग नहीं खुलने को गंभीर सेवादोष मानते हुए, मारूति सुजुकी इंडिया पर 2 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं कार विक्रेता केपी ऑटोमोटिव्स को कहा है कि वह परिवाद के खर्च 25 हजार रुपए का भुगतान करे। विपक्षीगण यह राशि 45 दिन में परिवादी को दे दें। आयोग ने कहा कि साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि परिवादी की कार सामने से एक मृत जानवर से टकराई और पलट गई,

- **एक्सीडेन्ट में एयर बैग नहीं खुलने को गंभीर सेवा दोष माना।**

लेकिन उसके दोनों एयरबैग नहीं खुले। ऐसे में विपक्षी कार कंपनी से परिवादी को हर्जा-खर्चा दिलवाना उचित होगा। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव और सदस्य हेमलता अग्रवाल व आशुतोष ने यह आदेश निर्माण नगर निवासी पीयूष शर्मा के परिवाद पर दिया।

परिवाद में अधिवक्ता विपुल शर्मा ने बताया कि परिवादी ने केपी ऑटोमोटिव्स से 31 अगस्त 2017 को मारूति की डिजायर कार खरीदी थी। कार 60 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर चलाने पर ही डगमगाने लगी। उसने सितंबर 2017 में कार की पहली सर्विस के दौरान कंपनी के वर्कशॉप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# पंजाब के मु.मंत्री ने एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को आमंत्रित किया

## ये मैच जालंधर व मोहाली में खेले जाएंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान अगले महीने होने वाली पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छह देशों में शामिल होगा। उन्होंने केन्द्र सरकार की उस नीति का हवाला दिया, जिसके तहत दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वी देशों को बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं के दौरान भारतीय धरती पर खेलने की अनुमति है।

27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता जालंधर और मोहाली के हॉकी स्टेडियमों में आयोजित होगी।

दो रिजर्व टीमों-ओमान और बांग्लादेश-को भी प्रतियोगिता के लिए नामित किया गया है, ताकि किसी टीम के हटने की स्थिति में उन्हें शामिल किया जा सके। एशियाई हॉकी महासंघ (एशियन हॉकी फैडरेशन) के तत्वावधान में होने वाली यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन पिछले साल इसका आयोजन नहीं हुआ था।

भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरेगा। भारत ने 2023 में चेन्नई और 2024 में चीन के हुलुनबुइर में यह खिताब जीता था।

- **पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने दोनों देशों के बीच हॉकी मैच खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था।**
- **पंजाब के मु.मंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर कहा कि दोनों देशों के एक-दूसरे के खिलाफ सीधे मैच खेलने पर प्रतिबंध है। पर, अगर दोनों देश किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए, आमने-सामने मैच खेलते हैं तो भारत की हॉकी नीति के तहत यह कोई आपत्तिजनक कृत्य नहीं है।**
- **पर, सवाल यह उठता है कि बाल की खाल निकाल कर भगवंत मान क्यों भारत-पाक मैच आयोजित करना चाहते हैं।**
- **यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष जूनियर वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया था।**
- **पर, शायद अब पंजाब में चुनाव के माहौल में किसी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, मु.मंत्री भगवंत सिंह मान मोहाली व जालंधर में भारत-पाक का मैच आयोजित कराने की पहल दिखा रहे हैं।**

पाकिस्तान की भागीदारी और उसके लिए जरूरी मंजूरियां लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर मान ने कहा, "बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कि द्विपक्षीय सीरीज (भारत और पाकिस्तान) आयोजित नहीं हो सकती हो।"

पाकिस्तान के संबंध में केन्द्र की खेल नीति उस देश के साथ किसी भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# वर्ष 2020 के निकाय चुनाव के मुकाबले दुगुने निकायों में बोर्ड बनाने की स्थिति में है भाजपा

## पिछली बार मात्र 31 प्रतिशत निकायों में ही भाजपा का बोर्ड था, जबकि इस बार 65 प्रतिशत निकायों में भाजपा स्वयं या निर्दलीयों के समर्थन से बोर्ड बना सकेगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 14 सितम्बर। राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में हुए चुनाव में इस बार भाजपा को पिछली बार से दुगुना जनादेश मिला है। वर्ष 2020 में केवल 31 प्रतिशत निकायों में ही भाजपा का बोर्ड था। वहीं, इस बार भाजपा 65 प्रतिशत निकायों में स्वयं या निर्दलीयों के समर्थन से बोर्ड बनाने की स्थिति में है, हालांकि ये आंकड़ा आगामी 21 सितम्बर तक और बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। माना जा रहा है कि नगर निगम में 10, नगर परिषद में 15 और नगरपालिका बोर्ड में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के "वन स्टेट-वन इलेक्शन" फार्मूले और प्रदेशभर में किए गए रोड शो को मिला जनादेश।**
- **माना जा रहा है कि जहाँ-जहाँ री-पोलिंग होनी है, वहाँ नगर निगम में 10, नगर परिषद् में 15 और नगरपालिका बोर्ड में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है।**
- **राजधानी जयपुर में लगातार 7वीं बार भाजपा का बोर्ड बनेगा, जयपुर के 2 टुकड़े करने के कांग्रेस के निर्णय को जनता ने नकारा।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश में पहली बार "वन स्टेट-वन इलेक्शन" की जो शुरूआत की और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय'

जयपुर, 14 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों में भाजपा की शानदार जीत पर प्रदेश की जनता का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर पोस्ट साझा करते हुए इस जीत को "झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय" करार दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन

- **प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर जनता को धन्यवाद दिया।**

राठौड़ व भाजपा राजस्थान को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि "नगर निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए प्रदेश की जनता-जनार्दन का हृदय से धन्यवाद। जनता के इस जनादेश ने एक बार फिर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# '75 जिलों के लिए 75 चुनाव घोषणा पत्र'

## सपा नेता अखिलेश यादव ने यूपी के अगले विधानसभा चुनाव के लिए नया मंत्र दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। समाजवादी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य के लिए एक ही घोषणापत्र जारी करने की परंपरा को तोड़ने जा रही है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक नए मंत्र पर अपनी मुहर लगा दी है, यूपी के 75 जिलों के लिए 75 घोषणापत्र।

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के "एक जिला, एक उत्पाद" अभियान से प्रेरणा लेते हुए तैयार की गई है। इसके तहत, उत्तर प्रदेश के हर जिले की अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, उम्मीदों और चुनौतियों को ध्यान में रखा जाएगा।

पार्टी नेताओं का कहना है कि "एक जिला, एक घोषणापत्र" का फार्मूला चुनाव से पहले हर जिले के लिए विशेष और स्थानीय स्तर पर केन्द्रित वादे तैयार करने में मदद करेगा।

माना जा रहा है कि इससे

- **अखिलेश का तर्क है, हर जिले की अलग परिस्थिति होती है। अलग राजनीतिक व प्रशासनिक अपेक्षा व प्राथमिकताएं होती हैं।**
- **अतः सपा 75 जिलों के लिए अलग-अलग 75 घोषणा पत्र जारी करेगी।**
- **इससे जिला स्तर पर जिले की जनसंख्या के अनुसार, अलग-अलग जातियों को टिकट दिए जा सकेंगे। पूरे राज्य के जातिगत समीकरण पर अगर टिकट बाँटे जाते हैं, तो कई जातियों के साथ अन्याय होने की संभावना रहती है।**

समाजवादी पार्टी को हर जिले में अपने उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिलेगी। हर जिले के लिए घोषणापत्र का तरीका वह नहीं होगा, जो पार्टी सत्ता में आने पर पूरे राज्य के लिए करने का वादा करती है। इसके बजाय, ध्यान इस बात पर होगा कि "पार्टी उस जिले को किस तरह बदलने की योजना बना रही है।"

जिलों के हिसाब से तैयार किया जाने वाला यह घोषणापत्र समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा दे सकता है। इससे हर जिले में अलग-अलग जातीय और सामुदायिक समीकरणों के अनुसार वादे करने में मदद मिलेगी, जो एक ही राज्य स्तरीय घोषणापत्र में संभव नहीं हो पाता।

2017 से समाजवादी पार्टी बड़े राजनीतिक दलों को सहयोगी बनाकर चुनाव लड़ती रही है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 11 फरवरी 2017 को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 10 सूत्री साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया था। इसमें सत्ता में आने पर दोनों दलों के साझा विकास लक्ष्यों की रूपरेखा बताई गई थी।

बाद में दोनों दलों ने चुनाव अभियान के लिए अपने-अपने अलग घोषणापत्र जारी किए।

इसी तरह 2019 में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। उस समय कोई साझा घोषणापत्र जारी नहीं किया गया। दोनों दलों ने अपने-अपने वादे अलग-अलग जारी किए। 2024 के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जयपुर, कोटा, जोधपुर के महापौर का चुनाव आगे सरका

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 14 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नगरीय निकायों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। आयोग की ओर से 19 अगस्त 2026

- **ईवीएम की तकनीकी खराबी के कारण कुछ बूथों के परिणाम नहीं आने पर निर्वाचन आयोग का निर्णय।**

को नगरीय निकाय आम चुनाव, अगस्त-सितंबर 2026 का कार्यक्रम जारी किया गया था।

मतगणना के दौरान, नगर निगम जोधपुर, नगर निगम कोटा, नगर निगम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# जाने-माने एआई विशेषज्ञ सैम ऑल्टमैन, मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के नडेला, बिल गेट्स, एआई के विकास की दशा व दिशा को नियंत्रित करना चाहते हैं

## पर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एकदम विपरीत, एकदम उल्टी बात कह रहे हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है-चिंता वास्तव में इस बात को लेकर है कि आर्टिफिशल इंटैनिजैंस मानव जाति के लिए कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। ये चिंताएं चार अलग-अलग स्तरों पर व्यक्त की जा रही हैं, हालांकि कभी-कभी पूरी जानकारी नहीं रखने वाले कुछ लोग इन चिंताओं को नकार भी देते हैं।

सबसे पहली और सबसे गंभीर चिंता उन लोगों की है, जो वास्तव में आर्टिफिशल इंटैनिजैंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के बारे में जानते हैं। उद्योग के नेता खुद इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि एआई क्या तबाही ला सकती है।

उद्योग के तीन सबसे जानकार लीडर अब खुलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमताओं और खास तौर पर एआई जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। डर यह है कि कुछ समय बाद शायद एआई, अपने बनाने वालों से भी आगे निकल जाए और उनकी तबाही तथा पूरी तरह विनाश का कारण बन जाए।

"ओपन एआई" के सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने चैटजीपीटी मॉडल और उसके आगे के संस्करण विकसित

- **ट्रंप के अनुसार, दशा व दिशा नियंत्रित करने की बात नितांत बेवकूफी है, बल्कि अमेरिका को अपनी सारी ताकत, साइन्टिफिक नॉलेज, आर्थिक व मानव संसाधन एआई को तेज गति से विकसित करने के लिए झोंक देना चाहिए।**
- **ट्रंप के अनुसार, अगर अमेरिका एआई के प्रचार-प्रसार व विकास को नियंत्रित करने की सोच में फंसा तो चीन इस क्षेत्र में भी बाजी मार ले जाएगा और यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होगा।**

किए हैं, ने सार्वजनिक रूप से यह आशंका जताई है कि एआई के विकास में, मौजूदा दौर में, जल्द ही ऐसी स्थिति आ सकती है, जब कंप्यूटर अपना खुद का नेटवर्क विकसित कर लें और इंसानों की मदद के बिना आपस में बातचीत करने लगें।

ऐसी स्थिति में एआई के पास इंसानों से कहीं अधिक बुद्धिमत्ता हो सकती है और वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है। इस क्षमता के साथ ये एआई इन्टरफेस मानवता को पूरी तरह खत्म करने का काम कर सकते हैं। इस संभावना से केवल सैम ऑल्टमैन ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि अपनी एआई कंपनी "एक्सएआई" चलाने वाले एलन मस्क ने भी एआई इण्डस्ट्री के रैगुलेशन की जरूरत पर जोर दिया है।

और अब सबसे शक्तिशाली एआई कंपनियों में से एक, "एंथ्रोपिक" और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने कहा है कि एआई के विकास की गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए उद्योग की प्रमुख कंपनियों और सरकारों के बीच कुछ समझ बननी चाहिए, ताकि एआई के आगे के विकास पर रोक लगाई जा सके।

इण्डस्ट्री में दूसरे लोग, जैसे "माइक्रोसॉफ्ट" के सत्या नडेला ने भी एआई के नियमन और उसके विकास की गति पर रोक लगाने की मांग की है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउण्डर और पूर्व सी.ई.ओ. बिल गेट्स ने भी इन विचारों का समर्थन किया है और वे भी इस बहस में शामिल हो गए हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पाकिस्तान ने जैश प्रमुख मसूद अज़हर पर ईनाम राशि 70 लाख रु. की

इस्लामाबाद, 14 सितम्बर। अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की समीक्षा बैठक होने वाली है। इससे ठीक पहले पाकिस्तान ने एक नई चाल चलते हुए

- **उसने यह कदम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बचने के लिये उठाया है।**

अपने ही पाले आतंकी पर 70 लाख का इनाम रख दिया है।

दरअसल, वैश्विक निगरानी संस्था की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल होने से बचने के लिए पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर इनाम की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)